

EDITORIAL

Sail/Swim or Sink

Head of Circles meeting held on 13th & 14th February, 2020 at BSNL Corporate office New Delhi. The Hon'ble Minister of Communication while addressing the meeting told that after revival package given to the BSNL we can either sails/swim or sink. He added that now the BSNL will get nothing from the Govt after this revival package and it has to be grown up at its own by taking the advantage of the package. He appealed the top rank officers to be more vigilant and increase the market share of BSNL, the important customers should be monitored closely by the officers. The Minister wanted to inculcate the work culture of the management and advised the way, but the ground reality is totally different. One side minister suggested the CGMs and GMs to visit each and every Gram Panchayat and meet to Surpanch to know the functioning of our services.

It is an open truth that the CGMs and GMs since joining at any circle they never come out from chamber to observe whether services are running or not? They do all the monitoring from their Chambers only.

We can understand the view and desire of MOC, but the ground realities are not at all touching the thought of MOC.

It is known to all intellectual citizen of country that the union Cabinet of India, approved a revival package for BSNL and it was announced that the Govt will provide Rs. 70,000 crore to BSNL for its revival – this- package was approved on 23-10-2019 but till February 2020 BSNL has not get any budgetary support from the Govt. The BSNL does not generate such a sufficient amount of revenue and it is unable to pay the salary of staff in time. At this juncture only financial support from Govt or loan from banks will help the BSNL to survive. While the package for revival was announced, all were very happy that within a short period of time the PSU will get some financial support from the Govt but the situation is just reverse. Now again the employees of BSNL feel once again cheated by the policy of the union Govt. The salient feature of revival package is the allotment of 4G spectrum, the issuing of sovereign guarantee bond for raising a fund of Rs. 8500/- crore for BSNL, Monetisation of assets and implementation of VRS. Out of these only VRS has been implemented through which 78569 BSNL employees have been sent out from the company and that too without paying a single paisa to them on the date of retirement on 31st January 2020. It is extremely painful that even after the declaration of revival package before four months 4G spectrum has not been allotted to BSNL and similar is the position of assets monetisation and issue of long term band with sovereign guarantee of the Govt.

The judgement of the apex court of India with regards calculation of the AGR has created uncertainty in Telecom sector and now Banks are not coming forward to invest in this sector. The abnormal delay in launching 4G spectrum and uncertain implementation of other revival package against the spirit of the version of our honourable Minister, either sail/swim or sink.

After implementation of VRS thousands of Telephone Exchanges and other installations are unmanned and locked. The proposal of NFTE (BSNL) to continue the existing employees on performance basis after VRS was heard by the management for consideration and implementation but the decision will come when boat will sink.

The non visionary approach of top management is the main hurdle in improvement of the services as well as revenue of the company without knowing the ground reality the orders are being issued for implementation In field area which is not implemented any where as it is not at need based. The existing employees after VRS are also living in apprehension for their future service and carrier as the HR issues are not being touched and resolved. The promotional examinations are delayed beyond expectations, the ban has been imposed on compassionate ground appointment. Thus the earned facilities of workers are being snatched. In this scenario how to implement the version either sail/swim or sink.

One can understand the view of the Hon'ble Minister as he has done a lot to get the revival package approved by the Cabinet but a sailor can sail the boat when it is fit for the sailing. One can swim to save the life upto his last breath but if the situation totally adverse neither the sailor nor the swimmer can cross the river and ultimately they have to sink.

The situation in BSNL is similar like a sailor as without any proper road map. The large number of employees have sent out on the plea that the services will be maintained by outsourcing which will take a long time to finalise the process.

At this stage, we should turn our vision to trust to learn the history and tradition of trade union unity through which a lot of concession and facilities were achieved by the workers. The NFTE (BSNL) is always played a vital role to unite the workers and today also it will be stand in forefront of the same.

पतवार चलाओ/ तैरो या डूब जाओ

दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2020 को परिमंडलीय प्रमुखों की बैठक बीएसएनएल निगमित कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक को माननीय संचार मंत्री ने संबोधित किया तथा कहा कि सरकार ने बीएसएनएल के लिए एक अति सराहनीय कदम उठाया है और पुनरूद्धार की अद्वितीय व्यवस्था की है, अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम नाव चलाकर या तैरकर नदी को पार करें या डूब जायें। उन्होंने कहा कि इस पुनरूत्थान पैकेज के अलावा सरकार कुछ भी देने नहीं जा रही है और बीएसएनएल को अपने बलबूते पर उठना होगा। माननीय मंत्री महोदय ने अधिकारियों से कार्यप्रणाली बदलने की सलाह दी और कहा कि परिमंडलीय प्रमुखों/मुख्य महाप्रबंधकों /महाप्रबंधकों को ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर अपने सेवाओं का जायजा लेना चाहिए वहां उन्हें सरपंचों से मिलकर सेवा संबंधित आवश्यकताओं को समझना चाहिए। उन्होंने बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आह्वान किया।

यह खुला सत्य है कि कोई मुख्य महाप्रबंधक या महाप्रबंधक किसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से लेकर वहां से स्थानांतरण हो जाने तक अपने कार्यालय कक्ष के बाहर नहीं जाते हैं वे अपने वातानुकूलित कमरे से ही कार्य का अवलोकन करते हैं।

हम माननीय मंत्री जी के विचारों को समझ सकते हैं, परंतु सरजमीन पर स्थिति बिल्कुल भिन्न है।

ज्ञातव्य है कि संघीय मंत्री परिषद ने 20.10.2019 को बीएसएनएल के पुनरूत्थान के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया और कहा गया कि सरकार बीएसएनएल के पुनर्जीवन एवं उत्थान के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपये देगी। देश के तमाम समाचार माध्यमों के द्वारा इसे प्रसारित किया गया तथा देश के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक तक यह बात पहुंच गई कि सरकार ने बीएसएनएल जैसे राष्ट्र उपयोगी संगठन को सत्तर हजार रुपये की मदद देने जा रही है, परंतु घोषणा के चार माह बाद भी बीएसएनएल को सरकारी कोष से एक पैसा भी नहीं दिया गया है। हालात यह हैं कि यह लोक उपक्रम अब उतनी भी राजस्व नहीं एकत्र कर पाती जिससे कार्यरत कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जा सके। ऐसे वक्त में सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग अथवा बैंक ऋण से ही कंपनी को जीवित रखा जा सकता है। सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलने तथा बैंकों द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में धन लगाने की अरुचि के कारण बीएसएनएल के सामने अंधकार है।

अक्टूबर 2019 में सरकार द्वारा घोषित रिवाइवल पैकेज के उपरांत समस्त बीएसएनएल कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन्हें लगा कि तुरंत सरकार आर्थिक मदद देकर हमारे सेवाओं को दुरुस्त कर देगी, परंतु विपरीत स्थिति ने सबों के मनसूबों पर पानी डाल दिया और एक बार फिर इस लोक उपक्रम के कर्मचारी सरकारी नीतियों के मकड़जाल में फंसा हुआ और ठगा हुआ महसूस करने लगे। रिवाइवल पैकेज में क्या देने को कहा गया था इस पर टिप्पणी आवश्यक है। देश में संचालित सभी निजी दूरसंचार प्रचालन में संलग्न कंपनियों ने तीन वर्ष पूर्व से 4जी स्पेक्ट्रम की सेवा उपभोक्ता को प्रदान कर रही है, वहीं बीएसएनएल की सेवाएं आज भी 2जी एवं 3जी पर संचालित हैं, फलतः उपभोक्ताओं का रुझान निजी कंपनियों की तरफ ज्यादा हुआ और बीएसएनएल की बाजारीय हिस्सा में गिरावट आती गई। बीएसएनएल में संचालित यूनियनों एवं एसोसिएशनों द्वारा लगातार संघर्ष के उपरांत सरकार के मंत्रिपरिषद ने अक्टूबर माह में रिवाइवल पैकेज को अनुमोदित किया जिसके तहत निम्नांकित सहयोग सरकार की ओर से देने की घोषणा की गई।

1. 4जी स्पेक्ट्रम का मुफ्त आवंटन।

2. 8500 करोड़ रुपये का बांड जारी करने हेतु सरकार द्वारा सोवरन गारंटी देने की बात कही गई।
3. बीएसएनएल के जमीन एवं संसाधनों की नगदीकरण से धन इकट्ठा करने की अनुमति।
4. कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने की बात कही गई।

उपयुक्त सभी बिंदुओं को छोड़कर सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन ने पूर्ण रूप से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का अथक प्रयास किया फलस्वरूप 78569 अधिकारी एवं कर्मचारी तथाकथित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया और उन्हें 31 जनवरी 2020 को बिना एक पैसा भुगतान किये यहां तक कि दो माह का वेतन बकाया रखते हुए सेवानिवृत्ति दे दी गई। अन्य बिंदुओं पर आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। इस स्थिति में माननीय मंत्री महोदय की चाहत की पूर्ति कैसे की जा सकती है।

वीआरएस लागू होने के बाद हजारों टेलीफोन एक्सचेंज एवं अन्य प्रतिष्ठान में आदमी के नहीं होने की वजह से ताले लटक रहे हैं। एनएफटीई (वीएसएनएल) ने प्रस्तावित किया था कि अगली सुदृढ़ व्यवस्था होने तक वीआरएस के माध्यम से सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य पर उनके कौशल के आधार पर रखने की व्यवस्था की जाये ताकि सेवाओं पर प्रतिकूल असर नहीं हो सके। हमारी बातें सुनी गई उस पर अमल करने का आश्वासन मिला परंतु लगता है उस पर जब तक फैसला आयेगा नाव डूब चुकी होगी।

उच्च पदस्थ प्रबंधन की अदुरदर्शिता एवं इच्छाशक्ति के अभाव के वजह से सेवाओं का विस्तार, गुणवत्ता एवं राजस्व बढ़ोतरी प्रभावित है। वे जमीन स्तरीय स्थिति का जायजा लिये बगैर आदेश पारित करते रहते हैं जो सरजमीन पर प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि वे आवश्यकता आधारित नहीं होते हैं।

आधे से अधिक कार्यबल के विरमित होने के उपरांत बचे हुए कर्मचारी भी भय एवं चिंता ग्रसित हैं, उन्हें उनका भविष्य असुरक्षित महसूस हो रहा है।

कर्मचारियों की सेवा एवं उनके उन्नयन से संबंधित कार्य ठप्प है। परीक्षाएं दिसंबर 2019 तक स्थगित की गई थी परंतु उन्हें पुनः चालु नहीं किया जा रहा है। अनुकंपा पर आधारित नौकरी पर पाबंदी लगा दी गई है।

माननीय मंत्री महोदय के अभिप्राय को समझा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वीएसएनएल के पुनरुत्थान के लिए अथक प्रयास किया है तथा प्रतिबद्धता दुहराई है, परंतु एक नाविक, नाव को तभी उस पार ले जा सकता है जब नाव पूरी व्यवस्थित हो। अगर नाव डूबने की स्थिति होगी तो वह नदी में तैर कर पार करने का प्रयास करता है परंतु यह तत्कालिक स्थिति और कौशल पर निर्भर करता है अन्यथा अंततः उसे डूब जाना होता है।

बीएसएनएल को ऊपर उठाने या कठिनाई के पार ले जाने वाले नाविक की स्थिति भी यही है। बिना किसी प्रकार का रोडमैप तैयार किये और ठोस व्यवस्था के बगैर 78569 कर्मचारियों के कम हो जाने की स्थिति से निबटने की तैयारी किये बिना हम मझदार में कूद पड़े हैं। यह कहा गया की सेवाएं बाह्य संसाधनों से संचालित करेंगे परंतु इसके लिए काफी समय लगेगा।

इस नाजुक स्थिति में हमें अपना दृष्टि श्रमिक संघ के इतिहास एवं परंपरा की ओर ले जानी चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसी-कैसी विषम परिस्थितियों को झेलते हुए श्रमिक संगठनों ने अपने हक हकूक की रक्षा ही नहीं की है अपत्ति अनेकों सहूलियतें हासिल की हैं। आज संपूर्ण एकता ही समय की पुकार है और एनएफटीई सदैव इसके लिए अग्रणी भूमिका अदा करेगी।